



सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

अध्यक्षीय भाषण

ई. बालानन्दन

प्रिय कामरेड,

आइये हम आरंभ में उन मासूम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जो संघ परिवार के नेतृत्व में हिन्दू कट्टरपंथियों द्वारा 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद दहलाये जाने के बाद देश भर में फैली सांप्रदायिक हिंसा, तथा जनवरी, '93 के पूर्वार्द्ध में शिव सेना द्वारा लगाई गई सांप्रदायिक आग के शिकार हुए। इन जघन्य कांडों पर अपनी व्यथा व विरोध जताने के साथ ही साथ हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

सीटू की जनरल काउंसिल का यह अधिवेशन नागपुर में हुई जनरल काउंसिल बैठक के फैसले के अनुसार संगठनात्मक प्रश्नों पर विचार करने के लिए विशेष रूप से आयोजित की जा रही है। अयोध्या घटनाओं के बाद देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के बाद हमें यह बैठक स्थगित करनी पड़ी थी। भाजपा, आर.एस.एस., बिहिप गठबंधन द्वारा बाबरी मस्जिद गिराया जाना देश में वृत्ती हुई हिन्दू आक्रामकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम सभी घटनाक्रम से परिचित हैं और मैं उनके ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता। जबकि प्रधानमंत्री ममले को सुझाने के लिए वाचकीत में व्यस्त थे, संघ परिवार ने घोषणा कर दी कि वे अयोध्या में 6 दिसम्बर से कार सेवा करेंगे। वामपंथी लोकतांत्रिक पार्टियों के दबाव में सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई जिसका भाजपा व उसके चार मुख्य मंत्रियों ने वायकांट किया। एकता परिषद ने सर्वसम्मति से माकपा महासचिव कॉ. हरकिशन सिंह सुरजीत के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें बाबरी मस्जिद की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तथा वह भाजपा-आर.एस.एस. व बिहिप के उन्हीं नेताओं से बातचीत करती रही। इसी बीच उच्चतम न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया व उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादस्पद भूमि पर कोई निर्माण कार्य न होने दे तथा कार सेवक केवल भजन-

कीर्तन ही करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय में एक शपथ-पत्र दायर किया कि न्यायालय के आदेशों का पालन किया जायेगा। प्रकट में भाजपा नेतृत्व व उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जो दिखावा कर रहे थे कि वे अयोध्या में कोई अवैध निर्माण नहीं होने देंगे वह केवल केन्द्र सरकार को धोखा देने के लिए था ताकि केन्द्र कोई हस्तक्षेप न करे और वे मस्जिद को ध्वस्त करने की अपनी योजना पर अमल कर सकें। यह सच्चाई अब किसी से छुपी नहीं है।

मस्जिद का दहलाया जाना भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान को एक गहरा आघात था जिस पर भारत की एकता व अखंडता आधारित है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कल्याण सिंह ने इस बात का प्रबंध किया कि पुलिस व राज्य की प्रशासनिक मशीनरी मस्जिद को दहलाने के काम को सुगम बनाये। इस सारे मामले को जनता की नजर से छुपाये रखने के लिए मीडिया व प्रेस के कर्मचारियों पर विशेष गुटों द्वारा हमला किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक तबका भी मस्जिद गिराने के काम में लगा हुआ था।

इसके बाद देश में सांप्रदायिकता की जो आग भड़की वह अभीतक नहीं थकी। देश के विभिन्न भागों में 2 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई व संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। दम्बई, अहमदाबाद, कानपुर आदि जैसे औद्योगिक प्रदेश दंगे से प्रभावित हुए। केरल व पश्चिम बंगाल भी कुछ हद तक दंगे से प्रभावित हुए। अनेक स्थानों पर प्रशासनिक मशीनरी विशेष रूप से पुलिस सांप्रदायिक दरियों के आगे झुक गयी व उसने हिन्दू कट्टरपंथियों का साथ दिया। यदि लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा रोका न गया तो देश की प्रशासनिक मशीनरी व पुलिस सांप्रदायिक बायरस के इस प्रवेश से देश में फासीवादी शक्तियों के आधिपत्य का रास्ता खुलेगा। संघ परिवार का उद्देश्य देश भर में सांप्रदायिक प्रभुीकरण करना है जिसका वे कथित 'हिन्दू राष्ट्र' की स्थापना के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिसमें अन्य धर्मों के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उनकी हिन्दू की परिभाषा में भी केवल ऊँची जातियों के लोग ही



शामिल है। हरिजन, आदिवासी व पिछड़ी जातियों के लोगों को उनके आदेशी का पालन करना होगा। नरसिम्हा राव सरकार की अकर्मण्यता से संघ परिवार द्वारा मस्जिद गिराया जाना सुगम हो गया। जनता के जबर्दस्त दबाव के कारण नरसिम्हा राव सरकार को उत्तर प्रदेश तथा अन्य चार राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त करना पड़ा जिन्होंने ढाँचे को ध्वस्त किये जाने की योजना बनाने व उसे कार्यान्वित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। साथ ही उसे आर.एस.एस. व कुछ अन्य सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इन संगठनों पर केवल कागजी प्रतिबंध लगाया गया है और वास्तव में इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।

अयोध्या की विवादित भूमि के अधिग्रहण के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश तथा अनुच्छेद 141 के तहत मामले को उच्चम न्यायालय को सौंपना केवल हिन्दुत्व गैंग को बचने का रास्ता प्रदान करने के लिए तथा वास्तव में देश के धर्मनिरपेक्ष आधार को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है जो अयोध्या में दाव पर लगा हुआ है। अयोध्या में मन्दिर व मस्जिद निर्माण की सरकार की बहुप्रचारित योजना ने अभी तक उजाले का मुंह नहीं देखा।

कामरेड,

जनवरी के पूर्वार्द्ध में शिव सेना ने अपने सहयोगी गुटों के साथ मिलकर बम्बई में रह रहे अल्पसंख्यकों तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमला किया। मुस्लिमों द्वारा मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने सड़कों पर दैहिक को रोकते हुए महा आरती (पूजा) आरंभ कर दी। वहाँ से प्रशिक्षित हथियार गुट पूर्वनिर्धारित ठिकानों पर हमले के लिए भेजे गये। अगुी, बस्तियाँ और मुस्लिम बस्तियाँ हमले के ख़ास निशाने थे। बम्बई शहर में 10 दिन से ज्यादा समय तक हिंसा व आगजनी चलती रही। सरेआम लोगों पर

हमले किये गये तथा महिलाओं और बच्चों को नहीं बचसा गया। बम्बई में कार्यरत गैर-मराठी अल्पसंख्यकों पर भी हमले किये गये।

सरकारी अनुमान के मुताबिक लगभग 600 जाने गयीं। संपत्ति के नुकसान का कोई हिसाब ही नहीं है। अनुमात है कि कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। बम्बई की कांग्रेस (ई) सरकार अल्पसंख्यकों व गैर-मराठी लोगों की सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही। शिव सेना के हमलों से बचने के लिए लाखों लोगों ने बम्बई छोड़ दी। 30-40 हजार से अधिक मुस्लिमों को विभिन्न शरणार्थी शिविरों में ले जाया गया। बम्बई शहर को लकवा मार गया था तथा वह पूरी तरह से शिव सेना व उसके सहयोगी गुटों के नियंत्रण में था।

श्री बाल ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उनके लोग इन हमलों में शामिल थे व ऐसा मुस्लिमों को सबक सिखाने के लिए किया गया है तथा मुस्लिमों के लिए भारत में कोई स्थान नहीं होगा। उन्हें पाकिस्तान जाना होगा।

जो लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे थे उनकी मदद के लिए पुलिस व प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पहले की ही तरह इस बार भी पुलिस शिव सेना व उसके सहयोगी गुटों की मदद कर रही थी। हालाँकि सेना को बुला लिया गया था लेकिन उसे केवल मूक दर्शक बनाये रखा गया। पुलिस ने ज्यादातर मुस्लिमों को गिरफ्तार किया तथा गुण्डा तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस कंट्रोल रूम से भेजे गये टैप किए हुए संदेश न्यायालय के पास हैं, जिनसे बहुत कुछ पता चलता। पुलिस वालों से मुस्लिमों को कोई सुराज न देने के लिए कहा गया था। बम्बई की यह स्थिति थी, जनता से संबैधानिक व कानूनी सुरक्षा को आग में फेंक दिया गया था। अल्पसंख्यकों का सरकार पर से विश्वास उठ गया है। श्री जे. आर. डी. टाटा सहित अनेक उद्योगपति भी सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ उठ खड़े हुए तथा उन्होंने राज्य को आपातकाल घोषित करके सेना के हवाले करने की मांग की। मृच्छ मंत्री श्री नाईक व बम्बई के दोरे पर गये रक्षा मंत्री श्री शरद पवार कुछ नहीं कर सके। 10 दिन बाद बम्बई की यात्रा पर गये प्रधान मंत्री ने बम्बई में यह हत्याकांड करने वालों के खिलाफ एक वाक्य भी नहीं कहा।

अतः आज हम देख रहे हैं कि फासिस्ट गैंगों को देश के संविधान व लोकतंत्र से लेन देना दिया जा रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण यह है कि शिव सेना का अंश संगठन 'भारतीय कामगार यूनियन' मुस्लिम मजदूरों को फैक्ट्रियों में काम पर नहीं जाने दे रही है। गैर-मराठियों को भी इसी प्रकार की धमकियाँ दी जा रही हैं। इस प्रकार शिव सेना की धरती के पुत्र योजना कार्यान्वित हो रही है। इसके अलावा वे अनेक भागों में अंश संगठनों पर भय दिखाकर कब्जा करने के लिए हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि लोकतांत्रिक यूनियन एक होकर स्थिति का मुकाबला करने में असफल रही हैं। बम्बई जन-जीवन सामान्य होना अभी भी बाकी है।

आर.एस.एस. का नया हमला

24-25 जनवरी, 1993 को आर.एस.एस.-भाजपा नेतृत्व ने एक अन्य सन्त (संन्यासी) सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित किया। उन्होंने एक नया संगठन बनाया है। जिसका नाम राम-जन्मभूमि न्यास मंच है। स्वामी वामदेव इस संगठन के नये प्रमुख हैं। इस संगठन का घोषित लक्ष्य भारत में 'हिन्दू-राष्ट्र' की स्थापना और उसे सुगम बनाने के लिए केन्द्र में 'रामभक्तों' की सरकार बनाना है। उनके द्वारा पारित प्रस्ताव में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि हिन्दू संत ही ऋषि-मुनियों और महत्तों द्वारा स्थापित सदियों पुरानी परंपरा के सही उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अयोध्या 96 × 34 कि.मी. क्षेत्र का एक धार्मिक शहर होगा जिसमें फंजाबाद व मुस्लिम आबादी वाले अन्य इलाके शामिल होंगे। यह घोषणा की गयी है कि इस शहर में कहीं मस्जिद नहीं बनने दी जायेगी तथा इस क्षेत्र में मस्जिद बनाने के केन्द्र सरकार के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जायेगा। वे मांग कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान व बंगलादेश से सम्बन्ध समाप्त कर लेने चाहिए क्योंकि वे अयोध्या में मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ, भारत को 'सार्क' से भी हट जाना चाहिए।

हमें भाजपा-आर.एस.एस.-विहिप की इस नयी तकनीक पर ध्यान देना होगा कि वे नीतिगत घोषणाएं करवाने का काम हिन्दू संन्यासियों को सौंप रहे हैं। 6 दिसंबर को अयोध्या में कार सेवा आरंभ करने का फैसला भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। आर.एस.एस.-भाजपा नेता देश भर में संविधान में परिवर्तन के लिए प्रचार करते फिर रहे हैं। अपनी आपसी बातचीत में वे यह मांग करते हैं कि मुस्लिमों से वोट देने का अधिकार वापस ले लेना चाहिए। वे जिस हिन्दू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उसमें गैर-हिन्दू मुस्लिमों सिखों आदि के लिए कोई स्थान नहीं होगा। वे अपनी धार्मिक प्रभाव तथा हथियारों की ताकत का इस्तेमाल केन्द्रीय सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं। केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्त सम्मेलन को सभी सुविधाएं प्रदान की जबकि उसने राष्ट्रीय एकता अभियान के अन्तर्गत 2 फरवरी को वाराणसी में रैली करने की इजाजत नहीं दी। अतः नरसिम्हा राव सरकार अभी इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है तथा उनकी मदद कर रही है। उन्होंने 25 फरवरी को संसद के अधिवेशन के अवसर पर दिल्ली में विशाल रैली करने का फैसला किया था। लोगों को यह आशा का थी कि यह रैली दिल्ली में बम्बई जैसी परिस्थितियों पैदा कर सकती थी। सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका से नरसिम्हा राव सरकार ने इस रैली पर पाबन्दी लगा दी। उसके साथ ही उन्होंने हर तरह की रैली पर पाबन्दी लगा दी। लिहाजा राष्ट्रीय एकता अभियान द्वारा 30 मार्च को की जाने वाली रैली भी निरस्त हो गयी। तथाकथित तटस्थता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक सांप्रदायिकता-विरोधी रैली को संघ परिवार जैसी सांप्रदायिक ताकतों के साथ एक तराजू में तोला। हिन्दू सांप्रदायिक ताकतें आकामक हो रही हैं तथा

नरसिम्हा राव सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा हेतु कोई प्रयास नहीं कर रही है।

19 दिसम्बर को वामपंथी पार्टियों ने सभी धर्म निरपेक्ष विपक्षी दलों की एक बैठक की। इस बैठक में 'राष्ट्रीय एकता अभियान' का गठन हुआ जिसमें सीटू समेत सभी धर्म निरपेक्ष पार्टियों व जन संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

उन्होंने जनवरी में एक माह का कार्यक्रम बनाया जिसमें शपथ लेना, हस्ताक्षर करवाना व रैलियां करना शामिल था। अम-संगठनों की प्रायोजक समिति ने इस कार्यक्रम पर विचार किया तथा इसे स्वीकृति प्रदान की। सीटू केन्द्र ने इस बारे में इंटक के नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श करने के लिए कदम उठाये हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की शपथ पर हस्ताक्षर किए हैं तथा वे राष्ट्रीय एकता के लिए अभियान में शामिल होने को भी सहमत हो गये हैं। बम्बई की गड़बड़ियों के कारण कुछ क्षेत्रों में यह कार्यक्रम पूरी तेजी से नहीं चल सका। तथापि, हमने देखा कि लगभग सभी क्षेत्रों में सांप्रदायिकता-विरोधी तथा राष्ट्रीय एकता के लिए अभियान जोर पकड़ रहा है। सीटू को प्रत्येक केन्द्र में सांप्रदायिक व फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मजदूरों को सामंजस्य करने के काम में आगे रहना चाहिये।

पश्चिम बंगाल आयोजित 2 करोड़ लोगों की ऐतिहासिक 10,000 किलोमीटर लम्बी मानव श्रृंखला एक राह दिखाती है। यदि समुचित कदम उठाये जायें तो लोगों की चेतना को जागया जा सकता है। पटना में आयोजित रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। यह पटना में हाल में हुई रैलियों में सबसे विशाल रैली थी। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में राष्ट्रीय एकता अभियान द्वारा विशाल रैलियां आयोजित की जा रही हैं तथा हमें इनमें अधिक से अधिक लोगों को सामंजस्य करने के लिए प्रयास करने चाहिये। राष्ट्रीय एकता अभियान ने भाजपा की रैली के साथ ही साथ सब रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार की आलोचना की है। बहुरहाल, 30 मार्च की रैली के लिए तैयारी जारी है। हमें इसे नई दिल्ली में आयोजित विशालतम रैली बनाना है।

कुल मिलाकर, सांप्रदायिक व फासिस्ट ताकतें देश में लोकतंत्र व राष्ट्रीय एकता को नेस्तनाबूद करने में लगी हैं। अतः यह मजदूर वर्ग का दायित्व है कि वह हर कीमत पर लोकतंत्र व धर्म निरपेक्षता की रक्षा के लिए आगे आये।

सरकार की आधिकारिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष

कामरेड,

अम संगठनों की प्रायोजक समिति ने सरकार की आधिकारिक नीतियों के खिलाफ 16 जून को दूसरी अखिल भारतीय आम हड़ताल आयोजित की तथा 25 नवम्बर 1992 को नई दिल्ली में मजदूर वर्ग की अब तक की सबसे विशाल रैली आयोजित की। हड़ताल में लगभग 150 लाख मजदूरों ने भाग लिया। रैली में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के मजदूरों, केन्द्र व राज्य

सरकार के कर्मचारियों, बैंक व बीमा कर्मचारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के एक हिस्से ने भाग लिया। आई.पी.एफ. तथा रेलवे मेन्स फेडरेशन से जुड़े कर्मचारी भी बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए। उस रैली में एक घोषणा पत्र पारित हुआ जिसमें भविष्य के कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश थे। मैं उस घोषणा-पत्र के कुछ पहरे उद्धृत कर रहा हूँ।

“ऐसी शानदार एकता से शहरी व ग्रामीण जनता पर पड़ने वाले अर्थव्यवस्था के दुष्प्रभावों को रोकने की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। इससे जनता के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए तबका-वार तथा क्षेत्रीय व स्थानीय स्तरों पर आन्दोलन व संघर्ष छेड़े जा सकेंगे। इसके अलावा इससे देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा हेतु इन नीतियों के विरुद्ध संघर्ष व उचित बैंकाल्पिक नीतियों के विकास के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित केन्द्रीय, राज्य स्तरीय व क्षेत्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों व रैलियों के लिए बड़ी संख्या में जनता को आमंत्रित किया जा सकेगा।

इस नये मंच से देश भर में जन आन्दोलनों का समयबद्ध कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा जिसकी परिणति इन भयानक नीतियों के विरुद्ध जनता की सशक्त आवाज उठाले हुए भारत बन्द में होगी।”

प्रस्ताव में किसानों, कृषि मजदूरों, युवाओं व छात्रों आदि के जन संगठनों की भागेदारी आन्दोलन के आधार को और व्यापक बनाने की बात कही गयी है। साथ ही उसमें जन समर्थन जुटाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण भारत में आन्दोलन का आधार बनाना है। इस आधार पर संगठित आन्दोलन के लिए प्रायोजक समिति ने विभिन्न जन संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने का फैसला किया है। इस घोषणापत्र के सफल कार्यान्वयन से सरकार पर पीछे हटने और अपनी नीतियों को बदलने के लिए दबाव पड़ेगा।

कामरेड,

इस तथ्य के बावजूद, कि हम साल भर में दो सफल हड़तालें व दिल्ली में एक रैली कर चुके हैं, सरकार विश्व बैंक/मुद्राकोष के निर्देशों पर अमल करने के लिए कटिबद्ध है। सत्ता में आते ही नरसिम्हा राव सरकार ने मुद्रा कोष से ऋण के लिए संपर्क किया व यह तर्क दिया कि विदेशी मुद्रा के वर्तमान संकट से निपटने के लिए यह अत्यावश्यक है तथा यह एक अस्थायी प्रक्रिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक वर्ष की अवधि के अन्दर ही सरकार पुनः मुद्रा कोष से और अधिक राशि 9 बिलियन डॉलर का कर्ज ले रही है और इसके बदले में बैंक-कोष के आकाओं का दबाव भी बढ़ रहा है। बैंक-कोष के समक्ष किए गए वायदों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए सरकार उनके निर्देशों का आंख मीचकर पालन करती आ रही है, यह देखे बिना कि उनका देश के विकास व अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। 1991-92 तक वित्तीय घाटे को 8.4% से 6 प्रतिशत घटाने व वर्तमान वायदे के तहत इसे घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए सरकार पंचवर्षीय योजनाओं

के विकास मद में कटौती कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च में भारी कटौती की जा रही है। इसका विपरीत प्रभाव अब उद्योगों सहित अनेक क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो रहा है। अनेक उद्योग मंदी की परिस्थितियों के कारण अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रही हैं।

उदाहरण के तौर पर निर्माण गतिविधियों के विकास हेतु सरकारी अनुदान में कमी के बाद सीमेंट की सरकारी खरीद में 40 से 15 प्रतिशत तक कमी हो गयी है। परिणामस्वरूप भारत के सीमेंट उत्पादकों को सीमेंट का अपना उत्पादन 20% कम करना पड़ा। इंजीनियरिंग सहित अन्य उद्योगों की भी यही कहानी है।

औद्योगिक उत्पादन में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई तथा 1991-92 में इसमें वृद्धि 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वित्त वर्ष औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर 5 प्रतिशत रखी गयी है जो विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार अधिक से अधिक 3 प्रतिशत के करीब तक पहुंच सकती है। अभी भी अनेक उद्योगों में मंदी की परिस्थितियां बरकरार हैं।

आयात में भेदभावपूर्ण उदारता, विदेशी मुद्रा अनिव्यंजन व साथ उर्वरक व खाद्य वस्तुओं पर सहायिनी में कटौती का अनेक उद्योगों पर विपरीत असर पड़ रहा है। अनेक उर्वरक उद्योग व इंजीनियरिंग कंपनियां बन्द होने जा रही हैं। अन्न की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और आम आदमी का जीवन दूधभर हो गया है। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयर बेचना जारी है, जो कि निजीकरण की एक नयी प्रक्रिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागेदारी पर भी निजी बैंक व्यवस्था की अनुमति दी जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अब फेरा के बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मुद्राकोष के निर्देशों के अनुसार चलेया समिति ने अब आयात करों में और कटौती का सुझाव दिया है। इस प्रकार सरकार विश्व/बैंक मुद्रा कोष के आकाओं को प्रसन्न करने के सभी संभव उपाय कर रही है, जो कि भारतीय जनता के हितों के खिलाफ आ रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की मांगों पर बात करने से इंकार के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की दशा लगातार खराब हो रही है। इन्हें बी.आई.एफ.आर. के तहत बन्द करने का सुझाव बरकरार है अतः सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर अखिल भारतीय हड़ताल कार्यक्रम के लिए मजबूर हो रहे हैं।

श्रम मंत्रालय छंटनी व मिलजबन्दी की बाधाएं दूर करने व हड़ताल का अधिकार समाप्त करने के लिए औद्योगिक विवाद कानून में संशोधन करने जा रही है। अतः यह बेहद आवश्यक हो गया है कि दिल्ली घोषणा-पत्र, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है, के अनुसार मजदूर वर्ग को इन नीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए संगठित करें।

पूँजीवादी विश्व का बढ़ता हुआ संकट
कामरेड,

मैं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर घट रही घटनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल पूँजीवादी विश्व के बढ़ते हुए संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि सोवियत संघ के पतन के बाद तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति श्री जॉर्ज बुश ने घोषणा की थी कि वे एक नयी विश्व व्यवस्था का निर्माण करने जा रहे हैं जो उनके अनुसार,

मानवता के लिए समृद्धि लायेगी। लेकिन आज श्री बुश अमरीका के राष्ट्रपति नहीं और नये राष्ट्रपति, जिन्होंने अब कार्यभार ग्रहण किया है, आर्थिक मोर्चे पर गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। विकसित पूँजीवादी विश्व में 1992 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में औसत वृद्धि। प्रतिशत से कम रही। निम्नलिखित तालिका से इन देशों में शकल घरेलू उत्पादन (जी.डी.पी.), औद्योगिक उत्पादन व बेरोजगारी आदि के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है :

	औद्योगिक उत्पादन		जी.डी.पी.		बेरोजगारी	
	3 माह	1 वर्ष	3 माह	1 वर्ष	नवीनतम वर्ष	पूर्व
आस्ट्रेलिया	— 1.0	+2.1 अक्टू.	+1.4	+2.3 क्यू. 3	11.3 दिसं.	10.6
बेल्जियम	+ 0.5	+0.4 सितं.	एन.ए.	+1.6 क्यू. 3	8.6 दिसं.	7.8
कनाडा	+ 6.5	+0.7 अक्टू.	+1.4	+0.7 क्यू. 3	11.5 दिसं.	10.3
फ्रांस	— 2.7	— 3.8 नव.	+1.2	+1.4 क्यू. 3	10.5 नव.	10.0
जर्मनी*	— 7.5	— 5.1 नव.	+1.9	+0.9 क्यू. 3	7.4 दिसं.	6.3
हालैंड	— 5.7	— 3.3 नव.	+3.7	+1.3 क्यू. 3	4.5 नव.	4.5
इटली	— 11.5	— 1.4 अक्टू.	— 2.4	+0.8 क्यू. 3	10.0 दिसं.	10.0
जापान	— 10.2	— 8.2 दिसं.	— 1.5	+0.9 क्यू. 3	2.3 नव.	2.1
स्पेन	+ 0.6	— 0.6 सितं.	एन.ए.	+1.0 क्यू. 3	15.5 दिसं.*	15.2
स्वीडन	— 0.8	+0.7 अक्टू.	+2.3	+0.1 क्यू. 3	5.5 दिसं.*	3.5
स्विट्जरलैंड	+ 14.4	+1.7 नव.	— 0.5	— 0.6 क्यू. 3	4.2 दिसं.**	1.9
ब्रिटेन	+ 4.6	+0.1 नव.	+0.4	— 0.7 क्यू. 3	10.5 दिसं.	9.0
अमरीका	+ 3.6	+2.9 दिसं.	+3.4	+2.1 क्यू. 3	7.3 दिसं.	7.1

* राष्ट्रीय दर पर पिछले तीन माह के औसत का हाल के तीन महीनों से तुलना।

स्रोत : 'द इकोनॉमिस्ट, जनवरी 30, फरवरी 5, 1993

इससे पता चलता है कि सभी विकसित देशों में बेरोजगारी बढ़ रही है, औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है तथा सकल घरेलू उत्पादन में नाममात्र की वृद्धि हुई है। तथापि, उससे पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। जापान, अमरीका, जर्मनी व ब्रिटेन सहित सभी विकसित देशों के सिर पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। पृथक्-तः जापान को जबर्दस्त मंदी का खतरा है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि '92 के वर्ष में जापान में औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत से अधिक की कमी आयी है। जापान को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जो कि हमेशा शिखर पर रहता था गंभीर उतार पर है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में केवल धोमापन ही नहीं आया बल्कि 'इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ जापान' के अनुसार '92 में 10.6 प्रतिशत की कमी आयी है। जापानी कॉर्पोरेशंस धीरे-धीरे काम घटा रहे हैं और हजारों लोग बेकार होते जा रहे हैं।

1992 में दिवालियापन तीन गुना बढ़ गया। 'केटरेशन ऑफ बेंक्स 'एसोसिएशन ऑफ जापान' ने भी घोषणा की कि जिन कंपनियों का बैंक से कामकाज रुका हुआ है उनकी आर्थिक देनदारियां 2.9 प्रतिशत अर्थात् 4.32 ट्रिलियन येन यानि

34.4 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गयीं हैं। जापान व अमरीका के बीच औद्योगिक युद्ध तेज हो रहा है। श्री क्लिंटन ने घोषणा की है कि वे 1988 के सुपर 301 कानून जिसकी अवधि समाप्त हो गयी है, पुनः जीवित कर सकते हैं। इसके तहत अमरीका किसी भी देश के आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी ग्रुपों के जापानी महानिदेशक ने कहा कि 'यदि अमरीका सुपर 301 के तहत जापान पर एक तरफा ढंग से बंधिषें लगाता है तो टोकियो इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। इस प्रकार जापान जो कि पूर्वी यूरोप का 'आश्चर्य' होता था, अब मंदी और दिवालियापन की ओर जा रहा है।

बेरोजगारी व मिलबंदी बढ़ रही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में उत्पादन का स्तर 1992 में निम्नतम बिन्दु पर पहुंच गया है जो कि पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है। यूरोपीय आर्थिक एकीकरण की पूरी योजना लागू नहीं हो सकती क्योंकि सभी देश गंभीर संकट से गुजर रहे हैं और वे अपने संकट से उबरने के लिए एक-दूसरे से जूझ रहे हैं। जर्मनी के 'घाघी-कार' व 'स्टील' उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। यूरोप

की सबसे बड़ी 'ऑटो-निर्माता' कम्पनी, वोल्क्सवैगन ए.जी., ने 1993 तक अपने 2,73,000 कर्मचारियों में से 30,000 कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। जर्मनी का स्टील उद्योग भी गंभीर संकट में है। पूर्वी जर्मनी व सोवियत संघ में बनने वाला सस्ता स्टील उससे प्रतिस्पर्धा कर रहा है तथा वे मांग में आयी कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं व बेरोजगारी में वृद्धि बड़ी मात्रा में होने की आशंका है। 1993 में जर्मनी में कारों की बिक्री में 18 प्रतिशत तक की कमी आने की संभावना है।

अखबारों की रिपोर्टों के अनुसार, क्लिंटन प्रशासन और उसके सहयोगियों का जनवरी मध्य में आमना-सामना हो गया जब वाणिज्य विभाग ने घोषणा की कि यूरोप की प्रमुख औद्योगिक ताकतों सहित 19 देशों ने वेहद कम दाम पर अमरीका में स्टील भेज कर अमरीकी व्यापार कानून का उल्लंघन किया है। अतः अमरीकी सरकार 'यूरोपीय दूरसंचार व ऊर्जा उत्पादन उद्योग पर भी प्रतिबंध लगाने का इरादा रखती है।

अमरीका में स्थिति और भी खराब है। अनुमान कुल अमरीकी निगमों में से 25% निगम अपने उत्पादन लक्ष्यों में भारी कमी करने व श्रम शक्ति को घटाने की योजना बना रहे हैं। स्टील व ऑटो-उद्योग आर्थिक रसातल में जा रहे हैं। अमरीका में मंदी की ऐसी गंभीर स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। अनेक उद्योग अपना केन्द्र अन्य देशों में स्थानांतरित कर देने को कोशिश कर रहे हैं जहाँ श्रम लागत कम है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अमरीकी सरकार ने एक नया विभाग खोल दिया है। अमरीका में बेरोजगारी 7.5% बतायी जाती है जो कि हाल के वर्षों में अधिकतम है। लेकिन निगम प्रबंधकों द्वारा श्रम शक्ति घटाने संबंधी घोषणाएं रोज की जाती हैं।

अमरीका का विशालतम उद्योग आई.बी.एम. गंभीर संकट का सामना कर रही है। कम्पनी के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं आयी। उन्होंने 25,000 से अधिक रोजगार समाप्त करने व अनेक देशों में अपनी शाखाएं बन्द करने का फैसला किया है। इसी प्रकार सीबर्स रोबक एण्ड कं. ने भी 40,000 रोजगार समाप्त करने का फैसला किया है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है अमरीका ने जर्मनी, जापान व ब्रिटेन आदि के खिलाफ व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया है। उससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बनाने का दावा घुल चाट रहा है और व्यापारिक युद्ध व आयात पर बंदियों आदि रोज की बात हो गयी है।

केवल दिसम्बर में ही, ब्रिटेन में 60,000 लोगों का रोजगार जाता रहा और आधिकारिक तौर पर बेरोजगारी 10.3 प्रतिशत यानि 30 लाख हो गयी। अनेक ब्रिटिश कंपनियों में संकट की स्थिति के कारण रोजगार में कटौती की जा रही

है।

पूँजीवाद के द्वारा विकास का दावा कहीं दिखाई नहीं देता और हर जगह उल्टा ही हो रहा है। जो देश समाजवादी व्यवस्था को त्याग आये हैं वे भी ऐसे ही संकटों का सामना कर रहे हैं जिनकी वे पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे अब देख रहे हैं कि बेरोजगारी व मूल्य-वृद्धि की स्थिति थोड़ी ही अवधि में ही असहनीय हो गयी है और विकसित देशों ने जिस मदद का बादा किया था वह भी नकार दे रहा है।

इस प्रकार, विश्व के सभी प्रमुख औद्योगिक देश मंदी से गुजर रहे हैं और गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। संकट-मुक्त पूँजीवाद दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस संकट से उबरने के लिए ये देश कई तरीके अपना रहे हैं। विश्व बैंक/मुद्रा कोष के माध्यम से यह संकट तीसरी दुनिया के देशों की ओर घकेला जा रहा है। इसके अलावा अमरीकी साम्राज्यवाद दूसरे देशों खासकर तेल-प्रधान देशों में सैनिक हस्तक्षेप करके भी प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। विश्व के विभिन्न भागों में जातीय व नस्ल-भेदी संघर्षों का उपयोग भी वह अपना प्रमुख स्थापित करने के लिए कर रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि संकट-मुक्त पूँजीवाद महज एक धोखा है और बहुसंख्यक समाज के लिए उसका अर्थ गरीबी व अभाव ही होता है। अतः हमें मजदूर वर्ग को समाजवाद के लिए संघर्ष करने के लिए शिक्षित करना होगा जिसे सीटू को गंभीरता से लेना चाहिये।

साम्राज्यवाद, खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद, जनता के दमन के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है तथा जैसा कि हमने ईराक के मामले में देखा संयुक्त राष्ट्र संघ को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अतः साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष हमारे कार्यक्रम में हमेशा शामिल होना चाहिये। हमें असलियत को उजागर करना चाहिये।

अन्त में, अपने देश में औद्योगिक-संकट का सामना करते हुए सीटू यूनियनों को मजदूरों को लामबंद करने के सभी संभव प्रयास करने चाहिये।

देश की एकता-अखंडता को चुनौती देने वाली आक्रामक सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष, सरकार की आर्थिक नीतियों व साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तथा मजदूरों की एकता मजबूत बनाने के संघर्ष को हमारे कार्यक्रम में हमेशा शामिल होना चाहिये।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप महासचिव द्वारा पेश की जा रही रिपोर्टों को स्वीकार करें व उसे समूह बनायें ताकि वह हमारे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश का काम दे, साथ ही संगठन को मजबूत बनायें ताकि वह नयी चुनौतियों का सामना कर सके। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद !

सीटू संगठन को मजबूत करने का संकल्प

पी.के. गांगुली

सीटू जनरल काउंसिल की 19 से 21 फरवरी तक बंगलौर में संपन्न विशेष बैठक इस लिहाज से उल्लेखनीय रही कि इसमें कामकाज के सभी पहलुओं के लिहाज से संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया, ताकि नयी चुनौतियों का सीटू कारगर ढंग से मुकाबला कर सके और भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए मार्गदर्शन की भूमिका अदा कर सके।

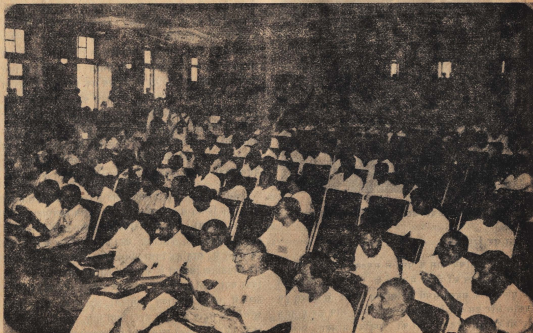
वास्तव में मार्च 1992 की नागपुर की जनरल काउंसिल बैठक में जो फैसला लिया गया था, उसके हिसाब से यह विशेष बैठक गत दिसंबर में ही आयोजित होनी थी। लेकिन, आर एस एम, भाजपा, विहिप, शिव सेना चोकड़ी द्वारा देश में भड़कायी गयी सांप्रदायिक विभीषिका के चलते दिसंबर में यह बैठक नहीं हो सकी।

जनरल काउंसिल की इस बैठक से पहले गत नवंबर में दिल्ली में हुई सीटू वकिंग कमेटी की बैठक में संगठन के कामकाज पर गहराई से विचार किया गया था और एक संगठन के रूप में सीटू के काम के विभिन्न पहलुओं को मजबूत करने के

लिए मूल्यवान सुझाव दिए गए थे। वकिंग कमेटी में हुई इस बहस और इस बहस के क्रम में आये ठोस सुझावों की रीजनी में ही इस जनरल काउंसिल बैठक के लिए सीटू सेक्रेटरीयट ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। जनरल काउंसिल की बैठक में 315 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सीटू अध्यक्ष ई बालानंदन द्वारा संगठन का झंडा फहराये जाने और शहीद स्तंभ पर फूलमालाएं चढ़ाकर शहीदों को याद किए जाने के बाद कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता, जनता दल के आर भी देशपांडे के स्वागत भाषण के साथ बैठक की कार्यवाही शुरू हुई।

अध्यक्षीय भाषण

ई बालानंदन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश में आर एस-एस भाजपा-विहिप द्वारा पैदा किए जा रहे सांप्रदायिक ध्वीकरण की विस्तार से चर्चा की, उन्होंने कहा कि इन ताकतों द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का डहकाया जाना हमारे देश में हिंदू सांप्रदायिकता के एक बहुत ही आक्रामक और महत्वपूर्ण चरण

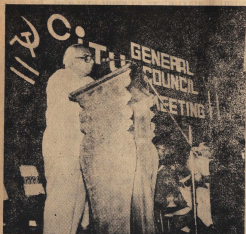


जनरल काउंसिल की बैठक का एक दृश्य।

का संकेत देता है। यह भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष आधार पर अबर्देस्त प्रहार है, जिस पर कि देश को एकता टिकी हुई है।

उन्होंने इन शक्तियों द्वारा 'हिन्दू राष्ट्र' का रास्ता साफ करने के लिए केन्द्रीय सत्ता के फासीवादी अधिग्रहण के खतरे की ओर इशारा किया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने विकसित पूंजीवादी देशों के बढ़ते हुए संकट के बारे में बताया जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष व विश्व बैंक का फायदा उठाते हुए अपना बोझ भारत व तृतीय विश्व के अन्य देशों पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। इन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में उन्होंने मुद्राकोष के निर्देश पर बनी आर्थिक व औद्योगिक नीतियों के खिलाफ किसानों, कृषि मजदूरों, छात्रों, युवाओं व महिलाओं को साथ लेकर संघर्ष छेड़ने की अपील की, जिसकी परिणति भारत बन्द में होगी, जैसा कि 25 नवम्बर को दिल्ली रैली में आह्वान किया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि संगठन को दृढ़ व शक्तिशाली बनाया जाये ताकि वह इन नयी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके। (पूरा अध्यक्षीय भाषण प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया है—सं०)



कामरेड एम. के. पंधे बैठक को संबोधित करते हुए

संगठन पर रिपोर्ट

सीटू महासचिव एम के पंधे ने संगठन पर एक रिपोर्ट जनरल काउंसिल की बैठक में बहस के लिए रखी, रिपोर्ट में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त संघर्ष के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए विकास और इस क्रम में युनाइटेड काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस (यू सी टी यू), ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति, सार्वजनिक क्षेत्र ट्रेड यूनियनों की समन्वय समिति और अब ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के गठन में सीटू की नेतृवकारी भूमिका की ओर ध्यान खींचा गया, रिपोर्ट में इस पर भी ध्यान

खींचा गया कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी संघर्ष में विभिन्न ट्रेड यूनियनों को खींचने में सीटू ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

वह्रहाल, इन सभी क्षेत्रों में सीटू की प्रगति को रेखांकित किया गया, जो संगठन के चौराहा विकास में बाधक बन रही है और उसे सामने मौजूद चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए समुचित रूप से आगे बढ़ने से रोक रही हैं। रिपोर्ट में आलोच-नात्मक ढंग से देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेड यूनियन आंदोलन के असमान विकास, हिंदी भाषी क्षेत्रों में भारी कमजोरी और जनतांत्रिक व सांस्कृतिक ढंग से कामकाज के मामले में सामने आये कुछ नकारात्मक क्षणों की पड़ताल की गयी, परंपरागत रूप से चली आ रही अनेक कमजोरियों से उबरने के लिए सामने आये अनेक मुद्दों पर भी इस रिपोर्ट में गौर किया गया। ताकि संगठन के कामकाज के सभी पहलुओं को मजबूत किया जा सके और आम मजदूरों को एक सही अर्थों में कार्यकर्ता-आधारित संगठन के रूप में सीटू के संचालन में मजदूरों को सक्रिय रूप से हिस्सेदार बनाया जा सके।

रिपोर्ट में सीटू के संविधान और उसमें स्पष्ट किए गए संगठन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की ओर ध्यान खींचते हुए रेखांकित किया गया कि ये लक्ष्य और उद्देश्य सीटू को अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से बुनियादी तौर पर भिन्न बनाते हैं। सीटू का उद्देश्य मजदूरों की रोजमर्रा की मार्गों के लिए लड़ने के साथ ही साथ मजदूर वर्ग को इसके लिए शिक्षित करना भी है कि सामाजिक रूपांतरण के लिए और पूंजीवादी शोषण के सामने तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाये। यह काम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मजदूर वर्ग सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया में नेतृवकारी भूमिका नहीं अदा करेगा। इस लक्ष्य को सामने रखकर उद्योग के संगठित और असंगठित, दोनों ही क्षेत्रों में मजदूरों के संघर्ष चलाये जाने की जरूरत है। लेकिन, जब तक मजदूरों को एक सुसंगठित संगठन में एकजुट नहीं किया जाता है, उनसे यह नेतृवकारी भूमिका अदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

इसी परिप्रेक्ष्य को सामने रखते हुए रिपोर्ट में सीटू की सांगठनिक स्थिति तथा उसके कामकाज के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की गयी। सीटू केंद्र, राज्य केंद्रों और सभी यूनियनों के स्तर पर संगठन के कामकाज पर विचार किया गया। इस सिलसिले में सामूहिक विचार-विमर्श के जरिये विभिन्न स्तरों पर सांगठनिक निकायों के कामकाज को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, आम मजदूरों के स्तर पर सभी मजदूरों की लामबंद करने में संगठन की राज्य कमेटियों और राज्य परिषदों की भूमिका के महत्व पर भी जोर दिया गया, यह भी रेखांकित किया गया कि किसी खास जिले में उद्योगों तथा यूनियनों की सघनता को देखते हुए जहाँ कहीं भी जरूरी हो, जिला स्तर पर कामकाज चलाया जाय और राज्य कमेटियों के फैसले के अनुसार जिला कमेटियों का गठन किया जाय। अबिल भारतीय केंद्र से

यूनियन के स्तर तक और यूनियन से अखिल भारतीय केंद्र तक संचार तथा जानकारीयों का आदान-प्रदान बनाये रखने को रिपोर्ट में भारी महत्व दिया गया, इसी प्रकार, केंद्र तथा राज्य स्तरों पर और जिला तथा यूनियन स्तरों पर भी विचार-धारात्मक अभियान तथा शिक्षा के कार्यक्रम चलाने और ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करने पर जोर दिया गया, रिपोर्ट में हिंदीभाषी क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और खास तौर पर इस क्षेत्र में विचारधारात्मक शिक्षा के काम को बढ़ाने और इस क्षेत्र में गतिविधियों का केंद्र के साथ तालमेल करने पर विशेष जोर दिया गया।

इन सबके साथ ही रिपोर्ट में कामकाज के अन्तर्गतिक तरीके, सामूहिक ढंग से कामकाज और नेताओं तथा कार्यकर्ताओं, दोनों के ही स्तर पर तमाम नौकरशाहीपूर्ण प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में कामगार महिलाओं के बीच काम पर और संबंधित तबकों की अपनी अलग मांगों के लिए संघर्ष की अनुग्राही के जरिये अल्पसंख्यक समुदाय तथा जातीय अल्पसंख्यकों को भी सीटू में खींचने पर जोर दिया गया, सीटू पत्रिकाओं को बेहतर बनाने और उनकी प्रसार संख्या बढ़ाने का महत्व भी अलग से रेखांकित किया गया।

सांगठनिक कामकाज के विभिन्न पहलुओं को मजबूत बनाने के लिए अनेक काम भी इस रिपोर्ट में बताये गये। रिपोर्ट में यह निश्चय व्यक्त किया गया कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संगठन को मजबूत बनाया जाय और उसी के अनुसार कार्यकर्ताओं का विकास किया जाय। इसी प्रकार, मजदूर वर्ग के विचार-धारात्मक शिक्षण के लिए तीन महीने के अंदर-अंदर व्याख्यान के नोट समेत पाठ्यक्रम तैयार करने और एक देशव्यापी शिक्षण कार्यक्रम बनाने का फैसला लिया गया। इसी प्रकार, राज्य इकाइयों से कहा गया है कि वे अपने कामकाज और जिला कमेटियों के कामकाज की आत्मालोचनात्मक समीक्षा तैयार करें, यूनियनों द्वारा चलाये जाने वाले संघर्षों की समीक्षा हो और उस पर राज्य स्तर पर विचार हो। राज्यों से कहा गया है कि हर वर्ष सीटू सदस्यता का लक्ष्य तय कर, सदस्यता में वृद्धोत्तरी के लिए अभियान चलायें, ताकि मुख्यस्थित ढंग से सदस्यता बढ़ायी जा सके। इसी तरह, उद्योगवार तालमेल को मजबूत करने और हर स्तर पर ट्रेड यूनियन जनवाद को वास्तविकता में उतारने के कदमों पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में इस पर भी जोर दिया गया कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए वैकल्पिक नीतियों पर विचार-विमर्श का भारी महत्व है।

रिपोर्ट पर बहस

रिपोर्ट पर हुई बहस में 54 जनरल काउंसिल सदस्यों ने हिस्सा लिया, चूँकि संगठन की वकिंग कमेटी में पहले ही इन प्रश्नों पर विचार हो चुका था और जरूरी मुसबाब दिये जा चुके थे, वंगलौर में हुई बहस में जनरल काउंसिल के सदस्यों ने ही

हिस्सा लिया। बहस में इतनी भारी संख्या में सदस्यों की हिस्सेदारी, हालत की जरूरतों के मुताबिक संगठन को बढ़ाने तथा मजबूत बनाने के प्रति सदस्यों के उत्साह को ही प्रतिबिंबित कर रही थी। बहस के क्रम में विभिन्न वक्ताओं ने एक संगठन के रूप में सीटू के कामकाज की आत्मालोचनात्मक समीक्षा की, सीटू की उपलब्धियों को रेखांकित किया, उसे देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन में अग्रणी बना दिया है, और उसके ट्रेड यूनियन एकता के अविचल ढंग से समर्थन करने के महत्व को रेखांकित किया, जिसका कमसद वर्ग-संघर्ष के रास्ते पर समूचे मजदूर वर्ग को लाना है।

बहरहाल, सीटू की उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ ही साथ विभिन्न वक्ताओं ने संगठन की कमजोरियों, घातियों तथा इस विकास के साथ ही साथ सामने आये कुछ नकारात्मक रूझानों की ओर भी ध्यान खींचा। इस लिहाज से उन्होंने ऐसे अनेक क्षेत्रों की ओर खासतौर पर ध्यान खींचा, जहाँ सीटू को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संगठित उद्योगों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम, ताकि मजदूरों के बीच सीटू की पकड़ मजबूत हो सके; असंगठित उद्योगों के विशाल क्षेत्र में काम; हिंदीभाषी क्षेत्र में काम; महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे राज्यों में काम, जो औद्योगिक दृष्टि से देश के सबसे सशक्त राज्यों में से हैं और इसके बावजूद वहाँ सीटू समेत समूचा ट्रेड यूनियन बहुत कमजोर है, कामगार महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बीच काम; किसान जनता के समर्थन की कार्रवाइयाँ आदि इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न वक्ताओं ने विचारधारात्मक शिक्षा के काम पर भी जोर दिया और कहा कि कार्यकर्ताओं का विकास और ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन, सीटू के एजेंडे का स्थायी हिस्सा होने चाहिए, उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि नौकरशाही की प्रवृत्ति पर कड़ा अंकुश लगाना चाहिए और केंद्र से लेकर यूनियन तक, हर स्तर पर सीटू में जनतांत्रिक ढंग से कामकाज होना चाहिए।

बहस में हिस्सा लेते हुए सभी वक्ताओं ने देश में एक भयावह फासोवादी ताकत के रूप में सामने आ रही साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष की जरूरत को रेखांकित किया। उनकी राय थी कि ट्रेड यूनियनों को एकजुट संघर्ष चलाना चाहिए, ताकि इन शक्तियों के फैलाव को रोका जा सके और औद्योगिक केंद्रों तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन को इनके असर से बाहर रखा जा सके। बहस में यह आम राय थी कि इन ताकतों के खिलाफ संघर्ष को सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष के समान ही सबसे आगे रखा जाना चाहिए और सीटू को मजबूत बनाया जाना चाहिए, ताकि वह इस दोहरी लड़ाई को एक साथ और कारगर ढंग से चला सके।

समाजवाद के लिए संघर्ष

रिपोर्ट पर बहस में हिस्सा लेते हुए जनरल काउंसिल सदस्यों ने यह भी रेखांकित किया कि सीटू की स्थापना समाजवाद के

लिए संघर्ष के लक्ष्य को लेकर हुई है। इसलिए, इसी आधार पर संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वर्गीय शक्तियों का संतुलन मजदूर वर्ग के पक्ष में मोड़ा जा सके। अनेक वस्तुओं ने ट्रेड यूनियन एकता पर विचार के क्रम में ट्रेड यूनियनों के पसिंध की स्थापना के महत्व पर जोर दिया, ताकि सरकार की नीतियों के खिलाफ और देश की संप्रभुता की हिकाजत के लिए ट्रेड यूनियनों और मजदूर वर्ग की एकता को और सुदृढ़ किया जा सके। एम के पंधे ने बहस का जवाब दिया, जिसके बाद यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

बैठक से यह समझ भी उभरकर आयी कि विभिन्न पहलुओं से संगठन को मजबूत बनाने का संघर्ष एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इससे जुड़े प्रश्नों पर निचले स्तरों पर भी गिचारा-विमर्श लगातार जारी रहना चाहिए। यह भी तय पाया गया कि इस रिपोर्ट पर राज्य स्तर पर विचार किया जाय, राज्य के अनुभवों तथा विचारों की घोषणा में उसे और समृद्ध बनाया जाय और उसके बाद वकिंग कमेटी की अगली बैठक में उसे अंतिम रूप दिया जाय।

इस रिपोर्ट के साथ जनरल काउंसिल ने दो प्रस्ताव भी स्वीकार किये, जिनमें एक सरकार की आर्थिक नीतियों पर था और दूसरा सांप्रदायिक शक्तियों पर पर। आर्थिक नीतियों संबंधी प्रस्ताव में इसका आह्वान किया गया कि दूसरे तमाम जनसंगठनों के साथ मिलकर आर्थिक नीतियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जाय, जो 25 नवंबर की रैली के आह्वान के अनुरूप भारत बंद के आयोजन में अपने चमोत्कर्ष पर पहुंचे। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ स्वीकार किये गये प्रस्ताव में यह आह्वान किया गया कि ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के अनुमोदन के अनुरूप राष्ट्रीय एकता अभियान की कार्रवाइयों में जबरदस्त हंग से हिस्सा लिया जाय और 30 मार्च को दिल्ली में होने जा रही रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियां की जाय।

समापन भाषण

जनरल काउंसिल की बैठक में हुई बहस का समापन करते हुए सीटू अध्यक्ष ई. बालानंदन ने कहा कि सीटू का गठन पूंजीवादी-भूस्वामी निजाम की अंतर्विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए हुआ है। जैसाकि पहले कहा जा चुका है, अपनी स्थापना के समय में ही सीटू तमाम ट्रेड यूनियनों को एक साझा मंच पर संगठित करने की कोशिश करती रही है और हममें यह बहुत हद तक कामयाब भी रही है। मजदूर-वर्ग में सीटू का अब अच्छा-खासा प्रभाव है। फिर भी, इस प्रभाव की अभिव्यक्ति पूरी तरह से सीटू के संगठन में नहीं हो पाती, जबकि यही आगे के विकास का आधार है। इसलिए, इस काम को सभी की पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। बालानंदन ने

रेखांकित किया कि अगर किसी उद्योग में सीटू की यूनियन में मजदूरों के एक खास हिस्से का ही तात्कालिक रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं, तब भी सीटू को सभी यूनियनों की मांगों को उठाना चाहिए और उद्योग के हालात के बारे में सभी मजदूरों को शिक्षित करना चाहिए। इस तरह से सीटू यूनियनों उद्योगों का नेतृत्व अपने हाथ में ले सकती हैं और यूनियन के आधार को मजबूत बना सकती हैं।

सीटू अध्यक्ष ने आगे कहा कि ट्रेड यूनियनों के जनतांत्रिक ढंग से संचालन का मामला सिर्फ औपचारिक जनतांत्रिक व्यवस्थाएं करने का नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि ट्रेड यूनियन ही वह संगठन है, जिसके जरिये मजदूर समाज की समस्याओं के बारे में शिक्षित होते हैं और जिसके जरिये वे समाज को बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका अदा करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। इसलिए, ट्रेड यूनियन नेताओं को इसके लिए कुसंत निकालनी ही चाहिए कि वे मजदूरों के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें और उन्हें शिक्षित करें। जो ट्रेड यूनियन नेता तीस-तीस, पैंतीस-पैंतीस यूनियनों के अध्यक्ष या इसी तरह के प्रमुख पदों पर हैं, उनसे इस लिहाज से मजदूरों के साथ ग्याय करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए, सीटू नेताओं को नेतृत्व उसी हद तक अपने हाथ में लेना चाहिए, जिस हद तक वे कारगर ढंग से इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। बजाय इसके कि तीस-तीस यूनियनों का एक ही नेता हो, होना यह चाहिए कि एक-एक यूनियन दर्जनों नेता पैदा करे।

ई. बालानंदन ने अंत में कहा कि आज भारत समेत दुनिया भर में पूंजीवादी देश इस संकट के दौर से गुजर रही हैं। विकसित पूंजीवादी देश इस संकट को अपने पक्ष में हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वे सारी दुनिया पर अपने ही समाधान थोपना चाहते हैं। दूसरी ओर मजदूर वर्ग तथा आम जनता अपने पक्ष में इस संकट को हल करना चाहती है। यही है आज के गहराते संकट के बीच तीखी होती लड़ाई का सार। इसलिए, जब तक आम मजदूरों के बीच मजबूत और जबरदस्त संगठन नहीं होगा, इस लड़ाई की सफलता के साथ आगे नहीं ले जाया जा सकता। बहरहाल यह लड़ाई निष्णायक तभी होगी, जब मजदूर वर्ग के बहुमत को इस संघर्ष में उतार दिया जाय। सिर्फ इसी तरह महत्वपूर्ण जनतांत्रिक प्रगति संभव है।

21 फरवरी को शाम को, जनरल काउंसिल बैठक के मौके पर बंगलौर के जुबली पार्क में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई हजार मजदूरों ने हिस्सा लिया। रैली को दूसरे लोगों के अलावा ई. बालानंदन, एम.के. पंधे तथा एम. सूर्यनारायण राव ने भी संबोधित किया।

सीटू जनरल काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव

कॉ. गणेश घोष

सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी और चित्तगाँव रेड के नेता कॉ. गणेश घोष के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन साम्यवादी आन्दोलन के विकास के लिए अर्पित कर दिया। वे माकपा की पश्चिम बंगाल राज्य समिति, पश्चिम बंगाल विधान सभा तथा संसद के भी सदस्य थे। बैठक कॉ. घोष को श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

कॉ. वीरेन दत्त

जनरल काउंसिल मीटिंग कॉ. वीरेन दत्त के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करती है। वे सीटू की त्रिपुरा राज्य समिति के महा-सचिव, कार्यसमिति के भूतपूर्व सदस्य तथा त्रिपुरा की बाममोर्चा के भूतपूर्व श्रम मंत्री थे। वे त्रिपुरा के साम्यवादी आन्दोलन के एक प्रतिष्ठित नेता व माकपा की त्रिपुरा राज्य समिति के सदस्य थे। बैठक कॉ. वीरेन दत्त को श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

शोक प्रस्ताव

जनरल काउंसिल मीटिंग पंजाब के जाने-माने साम्यवादी नेता कॉ. दलीपसिंह जोहा, गुजरात के जाने-माने साम्यवादी नेता कॉ. ठाकुरभाई शाह, तमिलनाडु से माकपा के प्रमुख नेता कॉ. एन.के. कुण्ठन, एन.एफ.पी.टी.ई. के पूर्व सचिव कॉ. के.ए. राजन जिन्होंने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन काउंसिल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वाटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व महा-सचिव कॉ. के.के. रॉय गांगुली, आल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के महासचिव का. के.एम. मथ्यू तथा पंजाब के माकपा नेता का. दलीप सिंह टपियाला के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करती है।

अयोध्या में भाजपा-आर.एस.एस.-विहिप-बजरंगदल के गठ-बंधन द्वारा बाबरी मस्जिद गिराये जाने के बाद तथा उसके पश्चात् शिव सेना द्वारा बम्बई में भड़काये दंगों में देश-भर में मारे गये लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है।

शहीदों पर प्रस्ताव

19-21 फरवरी, 1993 को नागपुर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो देश की एकता व अखंडता की रक्षा करते हुए आतंकवादियों द्वारा मारे गये।

बैठक उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए पुलिस हमलों में मारे गये।

सांप्रदायिक स्थिति पर प्रस्ताव

19-21 फरवरी, 1993 को बंगलौर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग आर.एस.एस.-भाजपा-विहिप बजरंगदल व शिव सेना द्वारा देश में पैदा की गयी सांप्रदायिक स्थिति पर गहरा दुःख प्रकट करती है।

बाबरी मस्जिद का डहाया जाना संविधान व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पर सबसे गहरा आघात है। इस घटना के बाद देश में अभूतपूर्व दंगे हुए जिनसे औद्योगिक केन्द्र भी प्रभावित हुए। इसके बाद शिव सेना ने बम्बई में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी। अल्पसंख्यकों व गैर-मराठी मजदूरों को फकिटियों व अन्य प्रतिष्ठानों में घुसने नहीं दिया जा रहा है।

फासीवादी तरीके से संघ परिवार व शिव सेना देश का सांप्रदायिक भूविकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ एक ओर संघ परिवार ने वाराणसी व मथुरा को मस्जिदों की गिराने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है वहीं दूसरी ओर शिव सेना ने बम्बई के अलावा कानपुर व लखनऊ में भी महा आरती करने की धोपणा की है। ये फासीवादी शक्तियाँ रैली पर प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए 25 फरवरी को दिल्ली रैली करने तथा बम्बई जैसी स्थिति पैदा करने पर तुली हुई है।

इस घटनाक्रम में नरसिम्हा राव सरकार बाबरी मस्जिद को सुरक्षा देने व इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में पूरी तरह असफल रही है। इसके बजाय उसने हर कदम पर उन शक्तियों से समझौता किया है जिससे उन्हें देश की एकता-अखंडता को खतरा पहुँचाने व संविधान की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। यह निन्दनीय है कि सरकार ने राष्ट्रीय एकता अभियान की रैली को भाजपा की रैली के साथ एक तराजू में तोला व अपनी तटस्थता प्रकट करने के लिए हर प्रकार की रैली पर प्रतिबंध लगा दिया।

संघ परिवार व शिव सेना की उनकी सांप्रदायिक गति-विधियों व सरकार की तुष्टिकर की नीति अपनाने की भत्सना करते हुए जनरल काउंसिल सीटू की सभी राज्य समितियों श्रम संगठनों से अपील करती है कि वे देश की एकता-अखंडता की रक्षा हेतु व सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष में देश के सभी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष व देशभक्त तबकों को संगठित करें।

बैठक इस बात की सराहना करती है कि इंटक ने भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष चलाने की शपथ पर हस्ताक्षर किये हैं। सभी राज्य समितियों को समान मुद्दों पर संघर्ष में श्रम संगठनों की एकता को मजबूत करने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए।

धर्म-निरपेक्ष विपक्षी दलों व जन-संगठनों का 'राष्ट्रीय एकता अभियान' इस संदर्भ में एक स्वागत योग्य कदम है। बैठक राष्ट्रीय

एकता अभियान को विशाल रैलियां करने व विभिन्न राज्यों में मानव श्रृंखलाएं आयोजित करने व 30 मार्च को दिल्ली में एक विशाल रैली करने के लिए बधाई देती है।

आर्थिक स्थिति पर प्रस्ताव

19-21 फरवरी, 1993 को बंगलौर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग देश की चारों ओर से खराब होती आर्थिक स्थिति पर गहरा ओभर व्यक्त करती है। विव्थ बैंक-मुद्रा कोष के निर्देश पर बनी नयी आर्थिक नीति के बारे में श्रम संगठनों की आशंकाएं सही साबित हुई हैं तथा सरकार यह भूटा प्रचार करती फिर रही है कि नयी आर्थिक नीति से देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच जायेगी।

देश की आर्थिक संप्रभूता से समझौता करते हुए विश्व-बैंक-मुद्रा कोष की शर्तों को मानकर अपनायी जाने वाली नीतियों के बारे में सरकार का बहुप्रचारित तर्क यह है कि भुगतान संतुलन की स्थिति से निवटने के लिए यह ऋण निःशुल्क आवश्यक था। लेकिन पिछले दो वर्षों में बढ़ते हुए आयात व व्यापार घाटे के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति और खराब हुई है। प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक आगामी वित्त वर्ष में आयात के 33.5 बिलियन डॉलर व निर्यात केवल 27.5 बिलियन डॉलर होने व उस प्रकार 7.00 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटा रहने का अनुमान है। यही नहीं विदेशी कर्ज अब 75.00 डॉलर हो गया है। सकल घरेलू उत्पादन व कर्ज का अनुपात 25 प्रतिशत हो गया है तथा कर्ज-अदायगी अनुपात भी 32 प्रतिशत हो गया है।

रिजर्व बैंक के हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था की गति घोमी पड़ रही है। अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति में स्पष्ट कमी आयी है। हर्म में स्थायी व अस्थायी उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं। अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं जैसे चाय, कॉफी, वनस्पति व बिस्किट आदि में 16.7 प्रतिशत की औसत कमी आयी है।

कार ढाँचे के बारे में चल रही समिति की सिफारिशें ग्रामीण अमीरों, भारतीय इजारेदारों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनुकूल हैं।

शेयर घोटाला व उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति के सम्मने आये तथ्यों से पता चलता है कि वित्तीय संगठनों व शेयर दलालों ने कैसा घोटालेपूर्ण व्यवहार किया व जनता के करोड़ों रुपये बर्बाद हुए।

मुद्रास्फीति की दर में आयी कथित कमी के बावजूद सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं व मुद्रास्फीति में कमी का बाजार भावों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। नियंत्रण हटा लेने के बाद इस्पात की कीमतों में भार गुना वृद्धि हो गयी है। कोयले पर से भी नियंत्रण हटाया जा रहा है तथा उसकी कीमतों में भी 17 प्रतिशत की वृद्धि होने जा रही है। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूँ की भुगतान कीमतों में भी वृद्धि हो गयी है।

शेयरों के अनिवेशन, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों व देशी उद्योगपतियों के प्रवेश व रोजगार कर्तवियों के माध्यम से निजीकरण अभियान औरों पर है। सरकार ने बैंकों के निजीकरण व बड़ी संख्या में विदेशी बैंकों के प्रवेश को हरी झंडी दिखा दी है। विदेशी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गयी है तथा घरेलू उत्पादों पर एक्ससाईज ड्यूटी बढ़ा दी गई जिससे घरेलू उत्पादों के दाम बढ़ जायेंगे व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय बाजार पर कब्जा करने में आसानी रहेगी। साथ ही घरेलू उद्योग बीमारी का शिकार होंगे। फेरा में संशोधन किया गया है व लगभग सभी पाबंदियाँ समाप्त कर दी गयी हैं। उसके परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पकड़ और मजबूत होगी।

आर्थिक मदद बन्द कर देने व पुरानी इकाइयों को पुनः जीवंत बनाने के लिए निवेश रोक देने के कारण अनेक इकाइयाँ तकनीकी दृष्टि से पिछड़ गयी हैं व बन्द होने के कगार पर हैं। उद्योग में खासकर लघु उद्योगों में औद्योगिक बीमारी खतरनाक गति से बढ़ रही है।

लिहाजा लाखों मजदूरों पर छंटनी और बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। और जैसे इतना ही काफी नहीं था इस लिए श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए उनमें निर्गम नीति को शामिल करके बैंक/कोष निर्देशों के अनुसार, हड़ताल के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है।

जनरल काउंसिल प्रायोजक समिति के इस फैसले का स्वागत करती है कि 15 नवम्बर की रैली के धोषणा-पत्र के मुताबिक भारत बन्द में परितण्ट होने वाले एक चरण-बद्ध कार्यक्रम के बारे में किसानों, कृषि मजदूरों, छात्रों, युवाओं व महिलाओं आदि के संगठनों से उनकी एक संयुक्त बैठक बुलाने के बारे में विचार विमर्श किया जाये। बैठक ने सभी राज्य समितियों, यूनियनों व फेडरेशनों से अपील की है कि वे 25 नवम्बर की रैली की अपील को सफल बनाने के लिए मजदूरों के सभी तबकों को लामबन्द करें।

ओ.आई.एल. इंडिया में पूर्ण हड़ताल

25 फरवरी, 1993 को ऑइल इंडिया के कर्मचारियों ने द्विपक्षीय समझौते को केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता न दिए जाने के खिलाफ देश भर में सांकेतिक हड़ताल की। यह समझौता 18 माह से इस मान्यता का इन्तजार कर रहा है। हड़ताल अभीतक पूर्ण थी। क्योंकि देश भर के कुल 8538 कर्मचारियों में से 8489 कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। ऑइल इंडिया की क्षेत्रीय यूनियनों की सम्मन्वय समिति ने प्रबंधकों से मांग की है कि वे उक्त समझौते को तुरन्त लागू करें अन्यथा मजदूर 72 घण्टे की राष्ट्रीय हड़ताल करने पर मजबूर हो जायेंगे जिसके लिए ओटोस दिया जा चुका है।